

**EXAM GENIUS**  
Presents  
**GENIUS**  
**CURRENT**  
**AFFAIRS**

**In Bilingual**  
**09 Jan 2026**



**India's No. 1 Platform for UPSC**  
**| SSC | BANK | RAILWAY Exam**

**Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !**



Ques: Asian Development Bank (ADB) provided ₹4,100 crore assistance to which state for Musi Riverfront Development Project Phase-I?

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने मुसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना चरण-I के लिए किस राज्य को ₹4,100 करोड़ की सहायता दी?

- A) Telangana / तेलंगाना
- B) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
- C) Tamil Nadu / तमिलनाडु
- D) Karnataka / कर्नाटक
- E) Maharashtra / महाराष्ट्र

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Asian Development Bank provided ₹4,100 crore (USD 500 million) to the Government of Telangana.
- एशियाई विकास बैंक ने तेलंगाना सरकार को ₹4,100 करोड़ (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) प्रदान किए।
- The amount was given to the Minister for Industries and Commerce, Government of Telangana.
- यह राशि तेलंगाना सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री को दी गई।
- The assistance is for Phase-I of the Musi Riverfront Development Project.
- यह सहायता मुसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना के प्रथम चरण के लिए है।
- The project aims to rejuvenate and restore the Musi River.
- इस परियोजना का उद्देश्य मुसी नदी का पुनर्जीवन करना है।





Ques: Who chaired the first meeting of the Payments Regulatory Board (PRB)?  
पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की?

- A) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- B) S Krishnan / एस. कृष्णन
- C) T Rabi Sankar / टी. रबी शंकर
- D) Aruna Sundararajan / अरुणा सुंदरराजन
- E) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The first meeting of the Payments Regulatory Board (PRB) was held in Mumbai under the chairmanship of RBI Governor Sanjay Malhotra.
- पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) की पहली बैठक मुंबई में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई।
- The Board reviewed the functioning of the Department of Payment and Settlement Systems and domestic and global payment systems.
- बोर्ड ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग तथा घरेलू और वैश्विक भुगतान प्रणालियों की समीक्षा की।
- The draft Payments Vision 2028 was presented for strategic guidance.
- ड्राफ्ट पेमेंट्स विजन 2028 प्रस्तुत किया गया।
- PRB was constituted after amendment to the Payment and Settlement Systems Act, 2007, effective from 9 May 2025.
- PRB का गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में 9 मई 2025 से प्रभावी संशोधन के बाद किया गया।
- PRB replaced the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS).
- PRB ने भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) का स्थान लिया।
- Members present included S Krishnan, Nagaraju Maddirala, Aruna Sundararajan, T Rabi Sankar, and Vivek Deep.
- बैठक में एस. कृष्णन, नागराजू मड्डीराला, अरुणा सुंदरराजन, टी. रबी शंकर और विवेक दीप उपस्थित थे।





## RECENT LOANS AND AGREEMENTS :

- **The International Finance Corporation (IFC) has provided a loan of ₹300 crore (about USD 30 million) to the Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) issued by Grihum Housing Finance Limited.**  
• अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जारी रेज़िडेंशियल मॉर्गेज-बैकड सिक्क्योरिटीज़ (RMBS) को ₹300 करोड़ (लगभग 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का ऋण प्रदान किया है।
- **The World Bank has provided a loan of ₹9,821 crore to the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL).**  
• विश्व बैंक ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) को ₹9,821 करोड़ का ऋण प्रदान किया है।
- **Five loan agreements worth over \$2.2 billion given by ADB to India to Support key national flagship programmes and state-level projects in skilling, renewable energy, healthcare, urban transport, and sustainable livelihoods**  
• एडीबी द्वारा भारत को कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शहरी परिवहन और सतत आजीविका के क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं और राज्य स्तरीय परियोजनाओं के समर्थन के लिए 2.2 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के पांच ऋण समझौते दिए गए हैं।
- **The Asian Development Bank (ADB) has approved a USD 240 million loan for the expansion of the Chennai Metro Rail network.**  
• एशियाई विकास बैंक (ADB) ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 240 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।
- **Petronet LNG Limited has received a loan of ₹12,000 crore. The loan has been extended jointly by State Bank of India (SBI) and Bank of Baroda.**  
• पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड को ₹12,000 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ है। यह ऋण भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया है।
- **The World Bank has approved \$600 million financing for two clean air programmes in Uttar Pradesh and Haryana.**  
• विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दो स्वच्छ वायु कार्यक्रमों के लिए कुल \$600 मिलियन का वित्तपोषण स्वीकृत किया है।





**Ques: Who has been appointed as the Chairman of ESAF Small Finance Bank?**

ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) R. P. Ramakrishnan / आर. पी. रामकृष्णन
- B) Karthikeyan Manickam / कार्तिकेयन मणिक्कम
- C) K. Paul Thomas / के. पॉल थॉमस
- D) Rajnish Kumar / रजनीश कुमार
- E) Shyam Srinivasan / श्याम श्रीनिवासन

Answer: Option B

**Explanation | व्याख्या:**

- Karthikeyan Manickam, former Executive Director (ED) of Bank of India, has been appointed as the Chairman of ESAF Small Finance Bank (ESAF SFB).
- बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक (ED) कार्तिकेयन मणिक्कम को ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- He replaced R. P. Ramakrishnan in this position.
- उन्होंने इस पद पर आर. पी. रामकृष्णन का स्थान लिया है।
- ESAF Small Finance Bank was established on 10 March 2017.
- ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 10 मार्च 2017 को हुई थी।
- The headquarters of ESAF Small Finance Bank is located in Thrissur, Kerala.
- ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय त्रिशूर, केरल में स्थित है।
- Shri K. Paul Thomas is the Managing Director and CEO of the bank.
- श्री के. पॉल थॉमस बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं।





**Ques: What major milestone was announced in the Mumbai–Ahmedabad High Speed Rail (MAHSR) project in Maharashtra?**

मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना में महाराष्ट्र में कौन सा प्रमुख मील का पत्थर घोषित किया गया?

- A) Completion of the longest underground tunnel in Gujarat / गुजरात में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग का निर्माण
- B) Breakthrough of the second mountain tunnel in Palghar / पालघर में दूसरी पर्वतीय सुरंग का ब्रेकथ्रू
- C) Inauguration of Virar bullet train station / विरार बुलेट ट्रेन स्टेशन का उद्घाटन
- D) Completion of the entire tunnel network / पूरे सुरंग नेटवर्क का पूरा होना
- E) Start of commercial operations of bullet train / बुलेट ट्रेन का वाणिज्यिक संचालन शुरू

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- Union Minister Shri Ashwini Vaishnaw announced the breakthrough of the second tunnel in Palghar, Maharashtra, marking the first mountain tunnel of the Bullet Train Project in the state.
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के पालघर में दूसरी सुरंग के ब्रेकथ्रू की घोषणा की, जो राज्य की पहली पर्वतीय सुरंग है।
- The breakthrough was achieved in the 1.5 km long mountain tunnel MT-5 between Virar and Boisar bullet train stations.
- यह उपलब्धि विरार और बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशनों के बीच 1.5 किमी लंबी पर्वतीय सुरंग MT-5 में हासिल की गई।
- Earlier, a 5 km underground tunnel between Thane and BKC was completed in September 2025.
- इससे पहले ठाणे और बीकेसी के बीच 5 किमी लंबी भूमिगत सुरंग सितंबर 2025 में पूरी हुई थी।
- The Mumbai–Ahmedabad High Speed Rail (MAHSR) project is 508 km long with a total tunnel length of 27.4 km, including 21 km underground and 6.4 km surface tunnels.
- MAHSR परियोजना की कुल लंबाई 508 किमी है, जिसमें 27.4 किमी सुरंगें शामिल हैं।
- The project includes eight mountain tunnels and connects major cities from Sabarmati to Mumbai across Gujarat, Dadra & Nagar Haveli, and Maharashtra.
- इस परियोजना में आठ पर्वतीय सुरंगें हैं और यह गुजरात, दादरा व नगर हवेली तथा महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों को जोड़ती है।
- The MAHSR spans approximately 508 kilometres, covering 352 km in Gujarat and Dadra & Nagar Haveli, and 156 km in Maharashtra

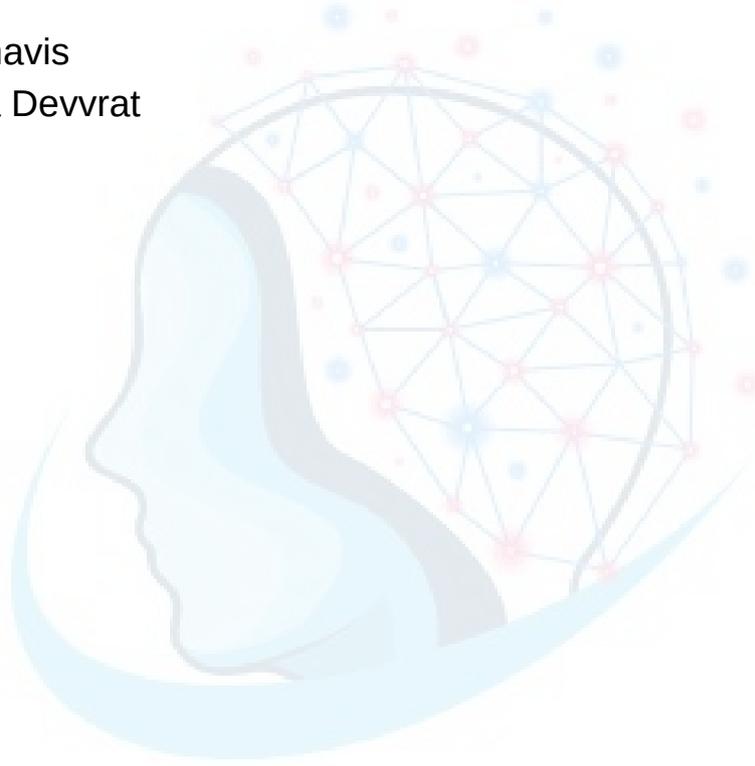




- महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजमार्ग (एमएचएसआर) लगभग 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 352 किलोमीटर गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली में तथा 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में स्थित है।

### About Maharashtra :

- Capital : Mumbai
- CM : Devendra Fadnavis
- Governor : Acharya Devvrat



EXAM  
Genius





**Ques: Who is set to become the oldest woman to play at the Australian Open after receiving a wildcard entry?**

वाइल्डकार्ड एंट्री मिलने के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने वाली सबसे उम्रदराज़ महिला कौन बनने जा रही हैं?

- A) Serena Williams / सेरेना विलियम्स
- B) Kimiko Date / किमिको डेट
- C) Venus Williams / वीनस विलियम्स
- D) Martina Navratilova / मार्टिना नवरातिलोवा
- E) Victoria Azarenka / विक्टोरिया अजारेंका

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Venus Williams (45) has been awarded a wildcard entry to the Australian Open.
- 45 वर्षीय वीनस विलियम्स को ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वाइल्डकार्ड एंट्री दी गई है।
- She will become the oldest woman ever to compete at the Australian Open.
- वह ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने वाली अब तक की सबसे उम्रदराज़ महिला खिलाड़ी बनेंगी।
- The Australian Open is the season-opening Grand Slam tournament.
- ऑस्ट्रेलियन ओपन सीजन की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है।
- Venus will play in the main draw for the first time since 2021.
- वीनस 2021 के बाद पहली बार मेन ड्रॉ में खेलेंगी।
- She is a seven-time Grand Slam singles champion and one of the greatest players in tennis history.
- वह 7 बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन और टेनिस इतिहास की महान खिलाड़ियों में से एक हैं।
- Venus Williams expressed excitement about returning to Australia and competing again.
- वीनस विलियम्स ने ऑस्ट्रेलिया लौटकर फिर से प्रतिस्पर्धा करने को लेकर उत्साह व्यक्त किया है।





**Ques: India and Pakistan exchanged the list of Nuclear Installations and Facilities for which consecutive time?**

भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं की सूची कितनीवीं बार लगातार आदान-प्रदान की?

- A) 33rd time
- B) 34th time
- C) 35th time
- D) 36th time
- E) 37th time

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- India and Pakistan exchanged the list of Nuclear Installations and Facilities simultaneously through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad.
- भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में कूटनीतिक माध्यमों से एक साथ परमाणु प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान किया।
- This marked the 35th consecutive exchange of such lists between the two countries.
- यह दोनों देशों के बीच इस प्रकार की सूची का 35वां लगातार आदान-प्रदान था।
- The agreement was signed on 31 December 1988 and came into force on 27 January 1991.
- यह समझौता 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित हुआ और 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ।
- The two countries also exchanged the list of prisoners under the Consular Access Agreement signed on 21 May 2008.
- दोनों देशों ने 21 मई 2008 को हस्ताक्षरित कांसुलर एक्सेस समझौते के तहत कैदियों की सूची का भी आदान-प्रदान किया।
- Pakistan handed over a list of 257 Indian prisoners, including 199 fishermen and 58 other civilians.
- पाकिस्तान ने 257 भारतीय कैदियों की सूची सौंपी, जिनमें 199 मछुआरे और 58 अन्य नागरिक शामिल हैं।
- As per the agreement, the exchange of prisoner lists is mandatory twice a year, in January and July.
- समझौते के अनुसार, कैदियों की सूची का आदान-प्रदान वर्ष में दो बार, जनवरी और जुलाई में अनिवार्य है।





**Ques: What is the main objective of the Lakhpati Didi Initiative under DAY–NRLM?**

DAY–NRLM के तहत लाखपति दीदी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Strengthening SHGs as institutions / SHG को संस्थागत रूप से मजबूत करना
- B) Providing subsidies to rural enterprises / ग्रामीण उद्यमों को सब्सिडी देना
- C) Enabling SHG women to earn ₹1 lakh or more annually on a sustainable basis / SHG महिलाओं को स्थायी रूप से ₹1 लाख या अधिक वार्षिक आय सक्षम बनाना
- D) Promoting urban self-employment / शहरी स्वरोजगार को बढ़ावा देना
- E) Creating rural industrial clusters / ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टर बनाना

**Answer:** Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- Lakhpati Didi Initiative is an outcome of the Deendayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihoods Mission, a centrally sponsored scheme of the Ministry of Rural Development.
- लाखपति दीदी पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू करता है।
- It focuses on individual SHG women and aims to enable them to earn at least ₹1,00,000 per year or ₹10,000 per month on a sustainable basis.
- इसका उद्देश्य SHG की व्यक्तिगत महिलाओं को स्थायी रूप से कम से कम ₹1,00,000 वार्षिक या ₹10,000 मासिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है।
- Income must be sustained for a minimum of four agricultural seasons or business cycles.
- यह आय न्यूनतम चार कृषि सत्रों या व्यवसाय चक्रों तक बनी रहनी चाहिए।
- There is no separate budget; all activities are funded under DAY–NRLM through training, capacity building, financial assistance and bank linkage.
- इसके लिए अलग बजट नहीं है और सभी गतिविधियाँ DAY–NRLM के तहत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, वित्तीय सहायता और बैंक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित होती हैं।





**Ques: Under which programme did President Droupadi Murmu launch the #SkillTheNation Challenge to promote AI education in India?**

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत में एआई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए #SkillTheNation Challenge किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया?

- A) Digital India Mission / डिजिटल इंडिया मिशन
- B) Skill India Mission – SOAR Programme / स्किल इंडिया मिशन – SOAR कार्यक्रम
- C) National AI Strategy / राष्ट्रीय एआई रणनीति
- D) PM Kaushal Vikas Yojana / प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- E) Samagra Shiksha Abhiyan / समग्र शिक्षा अभियान

**Answer:** Option B

**Explanation | व्याख्या:**

- President of India Droupadi Murmu launched multiple initiatives under the Skilling for AI Readiness (SOAR) programme, which is a key component of the Skill India Mission.
- भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्किलिंग फॉर एआई रेडिनेस (SOAR) कार्यक्रम के तहत कई पहलें शुरू कीं, जो स्किल इंडिया मिशन का हिस्सा है।
- She launched the #SkillTheNation Challenge and virtually inaugurated the IGNOU centre at Rairangpur, Odisha, at an event held at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi.
- उन्होंने #SkillTheNation Challenge की शुरुआत की और ओडिशा के रायरंगपुर में इग्नू केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया।
- The IGNOU centre aims to expand higher education and skill development in tribal-dominated regions of northern Odisha.
- यह इग्नू केंद्र उत्तरी ओडिशा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देगा।
- Under SOAR, AI learning is integrated into school education and teacher training for students of classes 6 to 12 and educators nationwide.
- SOAR के तहत कक्षा 6 से 12 के छात्रों और शिक्षकों के लिए एआई शिक्षा को स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण से जोड़ा गया है।
- Students complete three 15-hour modules, while teachers undergo a 45-hour module covering AI, machine learning, data literacy, and ethical use of technology.
- छात्र तीन 15-घंटे के मॉड्यूल करते हैं, जबकि शिक्षक 45-घंटे का मॉड्यूल पूरा करते हैं, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साक्षरता और नैतिक तकनीक उपयोग शामिल है।





**Ques: MOI-1 mini-satellite, developed by Hyderabad start-ups, is being launched as a co-passenger payload on which ISRO mission?**

हैदराबाद के स्टार्ट-अप्स द्वारा विकसित MOI-1 मिनी-सैटेलाइट को ISRO के किस मिशन में सह-यात्री पेलोड के रूप में लॉन्च किया जा रहा है?

- A) PSLV-C54
- B) Gaganyaan-G1
- C) PSLV-C62
- D) SSLV-D3
- E) LVM3-M4

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Two Hyderabad-based space-tech start-ups, TakeMe2Space and EON Space Labs, have developed and integrated a 14-kg Earth observation mini-satellite named MOI-1.
- हैदराबाद स्थित स्पेस-टेक स्टार्ट-अप्स TakeMe2Space और EON Space Labs ने MOI-1 नामक 14 किलोग्राम का अर्थ ऑब्ज़र्वेशन मिनी-सैटेलाइट विकसित और एकीकृत किया है।
- The satellite has been shipped to Sriharikota for launch as a co-passenger payload on ISRO's PSLV-C62 mission.
- यह उपग्रह ISRO के PSLV-C62 मिशन में सह-यात्री पेलोड के रूप में लॉन्च के लिए श्रीहरिकोटा भेजा गया है।
- MOI-1 will operate in Low Earth Orbit at an altitude of about 500 km and has an expected lifespan of 3–5 years.
- MOI-1 लगभग 500 किमी ऊँचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में कार्य करेगा और इसकी अनुमानित आयु 3–5 वर्ष है।
- Built in just six months, the satellite weighs only 14 kg and is 40–70% cheaper than comparable global satellites.
- केवल 6 महीनों में तैयार किया गया यह उपग्रह 14 किलोग्राम का है और समान वैश्विक उपग्रहों की तुलना में 40–70% सस्ता है।
- It carries a multispectral camera with 9 colour bands, 9.2-metre spatial resolution, and an 18.7-km swath.
- इसमें 9 रंग बैंड वाला मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा, 9.2 मीटर रिज़ॉल्यूशन और 18.7 किमी स्वाथ मौजूद है।
- MOI-1 supports in-orbit computing and AI-based data processing using an onboard NVIDIA GPU, reducing raw data transmission costs.
- MOI-1 इन-ऑर्बिट कंप्यूटिंग और NVIDIA GPU के माध्यम से AI-आधारित डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन लागत घटती है।





**Ques: Defence Laboratory Jodhpur (DLJ) of DRDO developed which portable water purification system?**

डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर (DLJ) ने कौन सा पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित किया है?

- A) SeaWater Desalination System (SWaDeS) / सीवॉटर डीसैलेनेशन सिस्टम (SWaDeS)
- B) AquaMarine Purifier / एक्वामरीन प्यूरिफायर
- C) Portable Reverse Osmosis Unit / पोर्टेबल रिवर्स ऑस्मोसिस यूनिट
- D) Marine Water Filtration Device / मरीन वॉटर फिल्ट्रेशन डिवाइस
- E) Saline Water Conversion Kit / खारे पानी रूपांतरण किट

**Answer:** Option A

**Explanation | व्याख्या:**

- Defence Laboratory Jodhpur (DLJ) under DRDO developed a portable water purification system called SeaWater Desalination System (SWaDeS), available in manual-operated and engine-driven variants.
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के तहत डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर (DLJ) ने सीवॉटर डीसैलेनेशन सिस्टम (SWaDeS) नामक पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की है, जो मैनुअल और इंजन-चालित दोनों प्रकार में उपलब्ध है।
- The engine-operated variant can desalinate seawater with TDS up to ~35,000 mg/L to below 500 mg/L for 20–25 soldiers, while the manual unit supports 10–12 personnel.
- इंजन-चालित संस्करण 20–25 सैनिकों के लिए लगभग 35,000 मिलीग्राम प्रति लीटर (mg/L) तक के TDS वाले समुद्री पानी को 500 mg/L से नीचे शुद्ध कर सकता है, जबकि मैनुअल यूनिट 10–12 लोगों के लिए पोर्टेबल है।
- Engine-operated systems can be set up within 2–3 minutes, and manual units are suitable for remote or power-scarce areas.
- इंजन-चालित प्रणाली 2–3 मिनट में स्थापित की जा सकती है, और मैनुअल यूनिट दूरदराज या बिजली-संकट वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त है।
- Applications include naval operations, coastal installations, inland saline lakes like Pangong Tso, and long-range patrols.
- इसका उपयोग नौसेना अभियानों, तटीय प्रतिष्ठानों, अंतर्देशीय खारे झीलों जैसे पांगोंग त्सो और लंबी दूरी की गश्ती में किया जा सकता है।





**Ques: Who became the youngest Indian and the second-youngest woman in the world to ski to the South Pole?**

दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला कौन बनीं?

- A) Kaamya Karthikeyan / काम्या कार्तिकेयन
- B) Malavath Purna / मालावथ पूर्णा
- C) Arunima Sinha / अरुणिमा सिन्हा
- D) Anshu Jamsenpa / अंशु जम्सेनपा
- E) Premlata Agarwal / प्रेमलता अग्रवाल

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- Eighteen-year-old Kaamya Karthikeyan, a skier from Mumbai, became the youngest Indian and the second-youngest woman globally to ski to the South Pole at an elevation of 2,385 metres.
- मुंबई की 18 वर्षीय स्कीयर काम्या कार्तिकेयन 2,385 मीटर ऊँचाई पर स्थित दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनीं।
- She started from 89° South and covered 60 nautical miles (115 km) in 11 days in temperatures of  $-30^{\circ}\text{C}$  across Antarctic ice.
- उन्होंने 89° दक्षिण से यात्रा शुरू कर  $-30^{\circ}\text{C}$  तापमान में 11 दिनों में 60 नौटिकल मील (115 किमी) की दूरी तय की।
- In 2019, she became the youngest girl to scale Mount Aconcagua (6,962 m), the highest peak in South America.
- 2019 में वह माउंट एकोकागुआ (6,962 मीटर), दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी, फतह करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनीं।
- In 2023, she became the youngest Indian to summit Mount Everest from the Nepal side.
- 2023 में वह नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनीं।
- In 2024–25, she completed the Seven Summits challenge, finishing with Mount Vinson in Antarctica.
- 2024–25 में उन्होंने अंटार्कटिका के माउंट विन्सन के साथ सेवन समिट्स चुनौती पूरी की।





**Ques: What is the Minimum Export Price (MEP) on natural honey extended by the Government till March 2026?**

सरकार द्वारा मार्च 2026 तक बढ़ाया गया प्राकृतिक शहद का न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) कितना है?

- A) \$2,000 per tonne
- B) \$1,800 per tonne
- C) \$1,600 per tonne
- D) \$1,400 per tonne
- E) \$1,200 per tonne

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Government of India has extended the Minimum Export Price (MEP) of \$1,400 per tonne on natural honey till March 31, 2026, as notified by the DGFT.
- भारत सरकार ने DGFT की अधिसूचना के अनुसार प्राकृतिक शहद पर \$1,400 प्रति टन का MEP 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया है।
- Earlier, the MEP was reduced from \$2,000 to \$1,400 per tonne in August to boost India's honey export competitiveness.
- इससे पहले अगस्त में भारत के शहद निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए MEP को \$2,000 से घटाकर \$1,400 प्रति टन किया गया था।
- Honey exports between April–October stood at 60,002 tonnes valued at \$117.97 million, with FY 2024–25 exports crossing 1 lakh tonnes worth \$206.47 million.
- अप्रैल–अक्टूबर के बीच शहद निर्यात 60,002 टन रहा, जिसका मूल्य \$117.97 मिलियन था। वित्त वर्ष 2024–25 में शहद निर्यात 1 लाख टन से अधिक रहा, जिसका मूल्य \$206.47 मिलियन था।
- Major export markets include the US, UAE, Saudi Arabia, and Qatar. India exports varieties like mustard, eucalyptus, litchi, and sunflower honey.
- प्रमुख निर्यात बाजारों में अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और कतर शामिल हैं। भारत सरसों, नीलगिरी, लीची और सूरजमुखी शहद जैसी किस्मों का निर्यात करता है।
- Uttar Pradesh is the largest honey-producing state (17%), followed by West Bengal (16%) and Punjab (14%).
- उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य है (17%), इसके बाद पश्चिम बंगाल (16%) और पंजाब (14%) हैं।





## Recent Appointment in Banking & Insurance Sector :

- **Hardeep Singh Ahluwalia** : interim Managing Director & CEO of Canara Bank
- हरदीप सिंह अहलूवालिया: केनरा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ
- **Ratan Kumar Kesh** : Executive Director (ED) of Bandhan Bank
- रतन कुमार केश : बंधन बैंक के कार्यकारी निदेशक (ईडी)
- **Brajesh Kumar Singh** : Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) of Canara Bank. (replaced K. Satyanarayana Raju)
- ब्रजेश कुमार सिंह : कनारा बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उन्होंने के. सत्यनारायण राजू का स्थान लिया है।)
- **Ms. Shahla Ayoub** : Independent Directors in J&K Bank for Tenure 3 Years (Dec 26, 2025 – Dec 25, 2028)
- सुश्री शाहला अयूब: जम्मू-कश्मीर बैंक में 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक (26 दिसंबर 2025 - 25 दिसंबर 2028)
- **Bibhu Prasad (BP) Kanungo**, former Deputy Governor of RBI : Non-Executive Chairman of the Board of IIFL Finance Limited
- भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर बिभु प्रसाद (बीपी) कानूनगो : आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
- **Ashwini Kumar Tewari** : Managing Director (MD) of the State Bank of India
- अश्विनी कुमार तिवारी : भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया
- **Ravi Ranjan (Deputy MD in SBI)** : Managing Director (MD) of State Bank of India (Replaced Vinay M. Tonse)
- रवि रंजन (एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक): स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) (विनय एम. टोन्से के स्थान पर नियुक्त)
- **Ajai Kumar Shukla** : Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of PNB Housing Finance
- अजय कुमार शुक्ला: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)





**Ques: India's traditional medical systems (AYUSH) were formally recognised in which international trade agreements?**

भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों (AYUSH) को किन अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में औपचारिक मान्यता दी गई है?

- A) India–UAE CEPA and India–UK FTA / भारत–यूएई CEPA और भारत–यूके FTA
- B) India–Japan CEPA and India–Australia ECTA / भारत–जापान CEPA और भारत–ऑस्ट्रेलिया ECTA
- C) India–Oman CEPA and India–New Zealand FTA / भारत–ओमान CEPA और भारत–न्यूज़ीलैंड FTA
- D) India–ASEAN FTA and India–Sri Lanka FTA / भारत–आसियान FTA और भारत–श्रीलंका FTA
- E) India–EU FTA and India–Canada CEPA / भारत–ईयू FTA और भारत–कनाडा CEPA

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Ministry of Commerce & Industry announced that India's traditional medical systems under AYUSH have been formally recognised in bilateral trade agreements.
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत की AYUSH के अंतर्गत पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में औपचारिक मान्यता दी गई है।
- These include the India–Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) and the India–New Zealand Free Trade Agreement (FTA).
- इनमें भारत–ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) और भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) शामिल हैं।
- The announcement was made during the 4th establishment anniversary celebrations of AYUSH Export Promotion Council (AYUSHEXCIL) in New Delhi.
- यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित AYUSH निर्यात संवर्धन परिषद (AYUSHEXCIL) के चौथे स्थापना दिवस समारोह के दौरान की गई।
- AYUSHEXCIL was registered on 4 January 2022 as a Section 8 company with the Registrar of Companies, Delhi.
- AYUSHEXCIL का पंजीकरण 4 जनवरी 2022 को दिल्ली के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ एक सेक्शन 8 कंपनी के रूप में किया गया था।





## Ques: Why did India and Bangladesh begin joint water measurement on the Ganga-Padma rivers?

भारत और बांग्लादेश ने गंगा-पद्मा नदियों पर संयुक्त जल मापन क्यों शुरू किया?

- A) Due to floods in Bangladesh / बांग्लादेश में बाढ़ के कारण
- B) To start a new river treaty / नई नदी संधि शुरू करने के लिए
- C) As the Ganges Water Sharing Treaty entered its final year / क्योंकि गंगा जल बंटवारा संधि अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर चुकी है
- D) For hydropower generation / विद्युत उत्पादन के लिए
- E) To resolve border disputes / सीमा विवाद हल करने के लिए

**Answer:** Option C

### Explanation | व्याख्या:

- India and Bangladesh initiated joint water measurement on the Ganga and Padma rivers as the 30-year Ganges Water Sharing Treaty entered its final year.
- भारत और बांग्लादेश ने गंगा और पद्मा नदियों पर संयुक्त जल मापन शुरू किया, क्योंकि 30 वर्षीय गंगा जल बंटवारा संधि अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर चुकी है।
- The measurements are being conducted 3,500 feet upstream of the Hardinge Bridge on the Padma River in Bangladesh and simultaneously at the Farakka point on the Ganga River in India.
- जल मापन बांग्लादेश में पद्मा नदी पर हार्डिंग ब्रिज से 3,500 फीट ऊपर और भारत में गंगा नदी पर फरक्का बिंदु पर समानांतर रूप से किया जा रहा है।
- The joint exercise aims to ensure accurate data sharing and transparency between the two countries.
- संयुक्त मापन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सटीक डेटा साझा करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
- The Ganges Water Sharing Treaty governs the distribution of dry-season flows of the Ganga between India and Bangladesh.
- गंगा जल बंटवारा संधि भारत और बांग्लादेश के बीच शुष्क मौसम में गंगा जल के वितरण को नियंत्रित करती है।





**Ques: “Azadi: Freedom. Fascism. Fiction” is written by which author?**

“आज़ादी: फ़्रीडम • फ़ासिज़्म • फ़िक्शन” पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है?

- A) Aravind Adiga / अरविंद अडिगा
- B) Amitav Ghosh / अमिताव घोष
- C) Arundhati Roy / अरुंधति रॉय
- D) Jhumpa Lahiri / झुम्पा लाहिरी
- E) Kiran Desai / किरण देसाई

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- “Azadi: Freedom. Fascism. Fiction” is a non-fiction book written by renowned Indian author Arundhati Roy.
- “आज़ादी: फ़्रीडम • फ़ासिज़्म • फ़िक्शन” प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय द्वारा लिखित एक नॉन-फिक्शन पुस्तक है।
- The book is a collection of essays written between 2018 and 2020.
- यह पुस्तक 2018 से 2020 के बीच लिखे गए निबंधों (Essays) का संग्रह है।
- It critically examines themes such as freedom, democracy, nationalism, fascism, and dissent in contemporary India.
- यह समकालीन भारत में स्वतंत्रता, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, फासीवाद और असहमति जैसे विषयों की आलोचनात्मक समीक्षा करती है।
- The title ‘Azadi’ symbolizes the idea of freedom, resistance, and civil liberties.
- ‘आज़ादी’ शीर्षक स्वतंत्रता, प्रतिरोध और नागरिक अधिकारों के विचार का प्रतीक है।
- The book reflects Arundhati Roy’s strong views on political power, state policies, minorities, and civil freedoms.
- यह पुस्तक राजनीतिक सत्ता, सरकारी नीतियों, अल्पसंख्यकों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर अरुंधति रॉय के सशक्त विचार प्रस्तुत करती है।
- The updated edition of the book is published by Penguin Random House India.
- पुस्तक का अपडेटेड संस्करण पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है।





## Recent News Headlines Related to DRDO

- **The Defence Research and Development Organisation (DRDO) successfully completed the User Evaluation Trials (UETs) of the Akash-New Generation (Akash-NG) surface-to-air missile system at the Integrated Test Range (ITR), Chandipur, Odisha.**  
• रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) में आकाश-न्यू जेनरेशन (आकाश-NG) सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए।
- **The Defence Research and Development Organisation (DRDO) handed over seven indigenous technologies developed under the Technology Development Fund (TDF) scheme to the Indian Armed Forces, including the Indian Army, Indian Navy, and Indian Air Force.**  
• रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने प्रौद्योगिकी विकास निधि (TDF) योजना के तहत विकसित सात स्वदेशी तकनीकों को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को सौंपा।
- **Defence Research and Development Organisation (DRDO) conducted a high-speed rocket-sled test of a fighter aircraft escape system at controlled velocity.**  
• रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने नियंत्रित वेग पर फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई-स्पीड रॉकेट-स्लेड परीक्षण किया।
- **Paras Defence & Space Technologies signed a Technology Transfer Licensing Agreement with DRDO for the Driver Night Sight (DNS) system used in T-90 battle tanks.**  
• पारस डिफेन्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने DRDO के साथ टी-90 टैंकों में उपयोग होने वाले ड्राइवर नाइट साइट (DNS) सिस्टम के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लाइसेंसिंग समझौता किया।
- **DRDO's Naval Science & Technological Laboratory (NSTL), Visakhapatnam, has successfully developed a new generation of Man-portable Autonomous Underwater Vehicles (MP-AUVs) designed for mine countermeasure missions.**  
• DRDO की Naval Science & Technological Laboratory (NSTL), विशाखापत्तनम ने माइन काउंटरमेज़र मिशनों के लिए नई पीढ़ी के मैन-पोर्टेबल स्वायत्त जल-निम्न वाहन (MP-AUVs) सफलतापूर्वक विकसित किए हैं।





**Ques: Why did the Government of India impose a safeguard duty on non-alloy and alloy steel flat products?**

भारत सरकार ने नॉन-अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट उत्पादों पर सेफगार्ड ड्यूटी क्यों लगाई?

- A) To increase export competitiveness / निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए
- B) To control domestic steel prices / घरेलू स्टील कीमतों को नियंत्रित करने के लिए
- C) To protect domestic industry from sudden import surge / घरेलू उद्योग को अचानक आयात वृद्धि से बचाने के लिए
- D) To comply with WTO penalty norms / WTO दंड मानदंडों का पालन करने के लिए
- E) To promote foreign steel imports / विदेशी स्टील आयात को बढ़ावा देने के लिए

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Government of India imposed a final safeguard duty on imports of non-alloy and alloy steel flat products following a DGTR investigation confirming a sudden surge in imports.
- DGTR जांच में अचानक आयात वृद्धि की पुष्टि के बाद भारत सरकार ने नॉन-अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट उत्पादों के आयात पर अंतिम सेफगार्ड ड्यूटी लगाई।
- The provisional safeguard duty has been converted into a definitive measure for three years with immediate effect.
- अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी को तुरंत प्रभाव से तीन वर्षों के लिए अंतिम ड्यूटी में बदला गया है।
- The duty rates are 12% from April 21, 2025 to April 20, 2026, 11.5% from April 21, 2026 to April 20, 2027, and 11% from April 21, 2027 to April 20, 2028.
- ड्यूटी दरें 21 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2026 तक 12%, 21 अप्रैल 2026 से 20 अप्रैल 2027 तक 11.5% और 21 अप्रैल 2027 से 20 अप्रैल 2028 तक 11% निर्धारित की गई हैं।





**Ques: Who has taken charge as the Vice Chief of the Air Staff of India?**

भारत के वायुसेना उपप्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है?

- A) Air Marshal Vivek Ram Chaudhari / एयर मार्शल विवेक राम चौधरी
- B) Air Marshal Narmadeshwar Tiwari / एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी
- C) Air Marshal Nagesh Kapoor / एयर मार्शल नागेश कपूर
- D) Air Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria / एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया
- E) Air Marshal Sandeep Singh / एयर मार्शल संदीप सिंह

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Air Marshal Nagesh Kapoor has assumed charge as the Vice Chief of the Air Staff (VCAS) of the Indian Air Force.
- एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के उपप्रमुख (VCAS) के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- He succeeded Air Marshal Narmadeshwar Tiwari, who superannuated after 40 years of service.
- उन्होंने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया, जो 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए।
- Air Marshal Kapoor is an alumnus of NDA, DSSC, and NDC, and is a skilled fighter pilot with over 3,400 flying hours on MiG-21 and MiG-29 aircraft.
- एयर मार्शल कपूर एनडीए, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं और मिग-21 व मिग-29 विमानों पर 3,400 से अधिक उड़ान घंटे का अनुभव रखने वाले कुशल लड़ाकू पायलट हैं।
- He has held key command, operational, instructional, and staff appointments, including AOC-in-C of Training Command and South Western Air Command, and has received multiple gallantry and distinguished service awards.
- उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमांड, ऑपरेशनल, प्रशिक्षण और स्टाफ पदों पर कार्य किया है, जिनमें ट्रेनिंग कमांड और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एओसी-इन-सी पद शामिल हैं, और उन्हें कई वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्राप्त हैं।





**Ques: The Employees' State Insurance Corporation (ESIC) extended SPREE 2025 till which date, allowing voluntary registration without past liabilities?**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने SPREE 2025 को बिना पिछली देनदारियों के स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए किस तिथि तक बढ़ाया है?

- A) 31 December 2025
- B) 15 January 2026
- C) 31 January 2026
- D) 28 February 2026
- E) 31 March 2026

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Employees' State Insurance Corporation (ESIC) announced a one-month extension of SPREE 2025, allowing employers and employees to register voluntarily without past liabilities until 31 January 2026.
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने SPREE 2025 को एक महीने के लिए बढ़ाते हुए 31 जनवरी 2026 तक बिना पिछली देनदारियों के स्वैच्छिक पंजीकरण की अनुमति दी।
- SPREE 2025 is implemented under the Employees' State Insurance Act, 1948 and was originally valid from 1 July 2025 to 31 December 2025.
- SPREE 2025 को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत लागू किया गया था और यह पहले 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक मान्य था।
- The scheme aims to expand social security coverage by promoting simplified and hassle-free registration of unregistered establishments and employees.
- इस योजना का उद्देश्य अपंजीकृत प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के लिए सरल और सुगम पंजीकरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है।
- It covers factories and establishments with 10 or more employees in ESI-notified areas, including shops, hotels, transport services, medical and educational institutions, municipal bodies, and workers earning up to ₹21,000 per month (₹25,000 for persons with disabilities).
- यह योजना ESI अधिसूचित क्षेत्रों में 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होती है, जिसमें दुकानें, होटल, परिवहन सेवाएँ, चिकित्सा व शैक्षणिक संस्थान, नगर निकाय तथा ₹21,000 (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ₹25,000) तक वेतन पाने वाले कर्मचारी शामिल हैं।



**Ques: Which country became the first in the world to officially end physical letter delivery?**

भौतिक पत्र वितरण आधिकारिक रूप से समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना?

- A) Sweden / स्वीडन
- B) Norway / नॉर्वे
- C) Denmark / डेनमार्क
- D) Finland / फिनलैंड
- E) Netherlands / नीदरलैंड

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Denmark's state-run postal service PostNord delivered its last physical letter, ending over 400 years of traditional mail delivery.
- डेनमार्क की सरकारी डाक सेवा PostNord ने अपना अंतिम भौतिक पत्र वितरित किया, जिससे 400 वर्ष पुरानी डाक परंपरा समाप्त हो गई।
- Denmark became the first country in the world to officially stop physical letter delivery in the digital age.
- डिजिटल युग में भौतिक पत्र वितरण समाप्त करने वाला डेनमार्क दुनिया का पहला देश बन गया।
- The decision reflects a sharp decline in letter usage due to digital communication, with PostNord delivering over 90% fewer letters in 2024 than in 2000.
- यह निर्णय डिजिटल संचार के कारण पत्रों के उपयोग में तेज गिरावट को दर्शाता है; 2024 में PostNord ने 2000 की तुलना में 90% से अधिक कम पत्र वितरित किए।
- Parcel delivery services will continue, driven by growth in e-commerce, and Denmark remains among the most digitally advanced countries with most government services online.
- ई-कॉमर्स की वृद्धि के कारण पार्सल डिलीवरी सेवाएं जारी रहेंगी, और डेनमार्क दुनिया के सबसे डिजिटल रूप से उन्नत देशों में शामिल है, जहां अधिकांश सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हैं।





## Recent Defence related appointments :

- **Air Marshal Nagesh Kapoor : 50th Vice Chief of the Air Staff (VCAS) (Replaced Air Marshal Narmdeshwar Tiwari)**

एयर मार्शल नागेश कपूर: वायु सेना के 50वें उप प्रमुख (वीसीएएस) (एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर)

- **Field Marshal Asim Munir : Pakistan's first Chief of Defence Forces (CDF)**

फील्ड मार्शल असीम मुनीर : पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स (CDF) नियुक्त किया

- **Major General Roman Gofman (currently Netanyahu's military secretary) : Director of Mossad, Israel's intelligence (Replaced David Barnea)**

मेजर जनरल रोमन गोफमैन (वर्तमान में नेतन्याहू के सैन्य सचिव): मोसाद के निदेशक, इज़राइल की खुफिया एजेंसी (डेविड बार्निया के स्थान पर)

- **Air Marshal Tejbir Singh : Director General (Inspection and Safety) (succeeds Air Marshal Makarand Bhaskar Ranade)**

एयर मार्शल तेजबीर सिंह: महानिदेशक (निरीक्षण और सुरक्षा) (एयर मार्शल मकरंद भास्कर रानाडे का स्थान लेंगे)

- **Praveen Kumar, currently Director General (DG) of the Indo-Tibetan Border Police (ITBP) : Additional charge of DG of the Border Security Force (BSF) (Replaced Daljit Singh Chawdhary)**

प्रवीण कुमार, वर्तमान में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक (डीजी): सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार (दलजीत सिंह चौधरी का स्थान)

- **Shri Raj Kumar Arora : Financial Advisor (Defence Services)**

श्री राज कुमार अरोड़ा: वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएँ)

- **Vice Admiral B Sivakumar : 40th Chief of Materiel (Replaced Vice Admiral Kiran Deshmukh)**

वाइस एडमिरल बी. शिवकुमार: 40वें चीफ ऑफ मैटेरियल (वाइस एडमिरल किरण देशमुख का स्थान लिया गया)

- **Vice Admiral Gurcharan Singh : Chief of Personnel of the Indian Navy**

वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह: भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख

विश्वजीत सहाय: रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) (राज कुमार अरोड़ा का स्थान लिया गया)





**Ques: PM-KUSUM 2.0, which the Union Government plans to roll out ahead of Union Budget 2026–27, is primarily aimed at what objective?**

केंद्र सरकार द्वारा बजट 2026–27 से पहले शुरू किए जाने वाले PM-KUSUM 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Large thermal power plants / बड़े ताप विद्युत संयंत्र
- B) Nuclear energy in rural areas / ग्रामीण क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा
- C) Decentralised solar energy in agriculture / कृषि क्षेत्र में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा
- D) Wind energy in coastal states / तटीय राज्यों में पवन ऊर्जा
- E) Hydropower irrigation projects / जलविद्युत सिंचाई परियोजनाएं

**Answer:** Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- Ahead of the Union Budget 2026–27, the Union Government is preparing to roll out PM-KUSUM 2.0, the next phase of the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM).
- केंद्रीय बजट 2026–27 से पहले केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के अगले चरण PM-KUSUM 2.0 को शुरू करने की तैयारी कर रही है।
- PM-KUSUM 2.0 reflects a renewed push towards decentralised solar energy solutions in the agriculture sector.
- PM-KUSUM 2.0 का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा समाधानों को और मजबूत करना है।
- The original PM-KUSUM scheme was launched in March 2019.
- मूल PM-KUSUM योजना मार्च 2019 में शुरू की गई थी।
- The current phase of PM-KUSUM is valid till March 2026 with a total outlay of ₹34,422 crore.
- PM-KUSUM का मौजूदा चरण मार्च 2026 तक लागू है, जिसका कुल परिव्यय ₹34,422 करोड़ है।
- The scheme aims to add around 34,800 MW of solar capacity across the country.
- इस योजना के तहत देश में लगभग 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है।
- Solar capacity addition will be achieved through decentralised grid-connected solar power plants, standalone solar pumps, and solarisation of existing grid-connected agricultural pumps.
- सौर क्षमता में वृद्धि विकेंद्रीकृत ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों, स्टैंडअलोन सोलर पंपों और ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण के माध्यम से की जाएगी।



**Ques: Which state hosted the Regional Artificial Intelligence Impact Conference held in December 2025?**

दिसंबर 2025 में आयोजित क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस राज्य ने की?

- A) Odisha / ओडिशा
- B) Telangana / तेलंगाना
- C) Maharashtra / महाराष्ट्र
- D) Karnataka / कर्नाटक
- E) Gujarat / गुजरात

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- Odisha hosted the Regional Artificial Intelligence Impact Conference on 19–20 December 2025.
- 19–20 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी ओडिशा ने की।
- The conference focused on AI in governance, AI-enabled public service delivery, and responsible, scalable and inclusive AI adoption.
- सम्मेलन का फोकस शासन में AI, AI-सक्षम सार्वजनिक सेवा वितरण और जिम्मेदार, विस्तारयोग्य व समावेशी AI अपनाने पर रहा।
- The event aligned with the Odisha AI Policy 2025 and supporting policies in FinTech, Global Capability Centres and Advanced Electronics.
- यह आयोजन ओडिशा AI नीति 2025 तथा फिनटेक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी नीतियों के अनुरूप था।
- The guiding principle of the conference was the Three Ps framework: Planet, People and Progress.
- सम्मेलन का मार्गदर्शक सिद्धांत श्री पी फ्रेमवर्क रहा: प्लैनेट, पीपल और प्रोग्रेस।





## Recent News Headlines Related to First in india and world :

**The first Gen Z Post Office in Jammu and Kashmir has been inaugurated at AIIMS Vijaypur.**

• जम्मू और कश्मीर में पहला Gen Z पोस्ट ऑफिस एम्स विजयपुर में उद्घाटित किया गया है।

**• Surat, widely known as India's "Diamond Capital", is on track to become the country's first fully slum-free city.**

• सूरत, जिसे व्यापक रूप से भारत की "हीरा राजधानी" के रूप में जाना जाता है, देश का पहला पूरी तरह से झुग्गी-मुक्त शहर बनने की राह पर है।

**• The Ophthalmology Department at the Army Hospital (Research & Referral), Delhi Cantt, performed India's first-ever 3D Flex Aqueous Angiography combined with iStent surgery.**

• दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) के नेत्र विज्ञान विभाग ने iStent के साथ भारत की पहली 3D फ्लेक्स एक्वियस एंजियोग्राफी सर्जरी की।

**• Tesla has set up its first charging station in India at the DLF Horizon Centre in Gurugram, Haryana.**

• टेस्ला ने भारत में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित डीएलएफ होराइजन सेंटर में स्थापित किया है।

**• VoxelGrids, a Zoho-backed startup, has developed and deployed India's first fully indigenous 1.5T MRI scanner at the Chandrapur Cancer Care Foundation, near Nagpur, Maharashtra.**

• जोहो समर्थित स्टार्टअप वॉक्सेलग्रिड्स ने महाराष्ट्र के नागपुर के पास चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.5T MRI स्कैनर स्थापित किया है।

**• India's first AI-driven Diabetic Retinopathy screening programme was launched on December 16, 2025.**

• भारत का पहला एआई-आधारित डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम 16 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया।

**• Tata Advanced Systems Limited (TASL) delivered the first batch of indigenously developed Wheeled Armoured Platform (WhAP) 8x8 vehicles to the Royal Moroccan Army (RMA).**





**LQues: Which Indian city, known as the “Diamond City,” is set to become the country’s first slum-free city?**

‘डायमंड सिटी’ के नाम से प्रसिद्ध कौन-सा भारतीय शहर देश का पहला स्लम-फ्री शहर बनने जा रहा है?

- A) Ahmedabad / अहमदाबाद
- B) Mumbai / मुंबई
- C) Surat / सूरत
- D) Jaipur / जयपुर
- E) Indore / इंदौर

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Surat, Gujarat’s second-largest city, is set to become India’s first slum-free city.
- गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर सूरत, भारत का पहला स्लम-फ्री शहर बनने जा रहा है।
- Surat is known as the “Diamond City” as it processes nearly 90% of the world’s diamonds.
- सूरत को “डायमंड सिटी” कहा जाता है क्योंकि यहां दुनिया के लगभग 90% हीरों की कटिंग-पॉलिशिंग होती है।
- It is also called the “Silk City” due to its large textile industry.
- विशाल वस्त्र उद्योग के कारण इसे “सिल्क सिटी” भी कहा जाता है।
- Surat is also known as “Suryapur” and “Green City” for its cleanliness and urban management.
- स्वच्छता और शहरी प्रबंधन के कारण सूरत को “सूर्यपुर” और “ग्रीन सिटी” भी कहा जाता है।
- The city is located on the left bank of the Tapi (Tapti) River.
- यह शहर ताप्ती (तापी) नदी के बाएं तट पर स्थित है।
- Historically, Surat was a major port and trading centre of western India.
- ऐतिहासिक रूप से सूरत पश्चिमी भारत का एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक नगर रहा है।





**Ques: What is the main focus of the NIRYAT PROTSAHAN sub-scheme under the Export Promotion Mission?**

निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत NIRYAT PROTSAHAN उप-योजना का मुख्य फोकस क्या है?

- A) Export subsidies for large exporters / बड़े निर्यातकों को निर्यात सब्सिडी
- B) Market branding and trade intelligence / बाजार ब्रांडिंग और व्यापार खुफिया
- C) Access to affordable trade finance for MSMEs / MSME के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच
- D) Logistics infrastructure development / लॉजिस्टिक्स अवसंरचना विकास
- E) Regulation of export pricing / निर्यात मूल्य निर्धारण का विनियमन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Under the Export Promotion Mission, two interventions have been launched under the NIRYAT PROTSAHAN sub-scheme to strengthen MSME exports.
- निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत MSME निर्यात को मजबूत करने के लिए NIRYAT PROTSAHAN में दो हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं।
- The government announced a ₹7,295-crore export support package, comprising a ₹5,181-crore interest subvention scheme and ₹2,114-crore collateral support, aimed at easing credit constraints for exporters, especially MSMEs, under the Export Promotion Mission framework.
- सरकार ने ₹7,295 करोड़ का निर्यात समर्थन पैकेज घोषित किया है, जिसमें ₹5,181 करोड़ की ब्याज सहायता योजना और ₹2,114 करोड़ का कोलेटरल समर्थन शामिल है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए ऋण उपलब्धता को आसान बनाना है।
- The first intervention provides interest subvention on pre- and post-shipment rupee export credit to reduce borrowing costs and ease working-capital constraints.
- पहला हस्तक्षेप प्री और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करता है।
- A base interest subvention of 2.75% is applicable, with additional incentives for exports to notified emerging or under-represented markets.
- 2.75% की आधार ब्याज सहायता दी जाएगी तथा उभरते बाजारों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है।
- Benefits apply only to exports under a notified positive list covering about 75% of tariff lines, with an exporter-wise cap of ₹50 lakh per IEC in FY 2025-26.



**Ques: The Ministry of Textiles extended the deadline for submission of fresh applications under which scheme till March 31, 2026?**

वस्त्र मंत्रालय ने किस योजना के तहत नए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई है?

- A) Technology Upgradation Fund Scheme / प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना
- B) Production Linked Incentive Scheme for Textiles / वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना
- C) National Technical Textiles Mission / राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन
- D) Integrated Textile Parks Scheme / एकीकृत वस्त्र पार्क योजना
- E) Amended Technology Upgradation Scheme / संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Ministry of Textiles extended the deadline for submission of fresh applications under the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles to March 31, 2026, from December 31, 2025.
- वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत नए आवेदनों की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है।
- As on September 9, 2025, 91 companies have been selected under the PLI scheme for textiles.
- 9 सितंबर 2025 तक वस्त्र PLI योजना के अंतर्गत 91 कंपनियों का चयन किया गया है।
- These companies account for investments of ₹7,731 crore, exports of ₹733 crore and turnover of ₹7,290 crore.
- इन कंपनियों द्वारा ₹7,731 करोड़ का निवेश, ₹733 करोड़ का निर्यात और ₹7,290 करोड़ का कारोबार दर्ज किया गया है।

**About PLI Scheme:**

- Launched : September 2021
- Tenure : 5 years from Financial Year 2021-22 (FY22) to FY26
- Outlay : Rs.10,683 crores
- Aim : To promote manufacturing, global competitiveness, and exports in selected segments of the textile industry





## Recent News Headlines Related to Books :

- "107 Days" : political memoir written by Kamala Harris.
- "107 डेज़" : कमला हैरिस द्वारा लिखी गई एक राजनीतिक आत्मकथा
- **'Mahamana Vangmay: The Collected Works of Pandit Madan Mohan Malaviya' (Second Series) : Released by Vice President of India, C.P. Radhakrishnan**
- 'महामाना वांग्मय: पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाएँ' (द्वितीय श्रृंखला): भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा विमोचित
- **Economic Empowerment of Bharat in the Modi Era : Professor Dr. Sikander Kumar, Member of Parliament**
- मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण: संसद सदस्य प्रोफेसर डॉ. सिकंदर कुमार
- **The Great Sanctions Hack : Former Reserve Bank of India(RBI) Governor Urjit Patel**
- प्रतिबंधों में हुई भारी सेंधमारी: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल
- **The Eleventh Hour : Salman Rushdie**
- द इलेवंथ आवर : सलमान रुश्दी
- **Sanatan Sanskriti Ki Atal Drishti : Shri Vasudev Devnani**
- 'सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि' : श्री वासुदेव देवनानी
- **Ghost-Eye : Amitav Ghosh**
- 'घोस्ट-आई' : अमिताव घोष
- **Biography 'Salman Khan: The Sultan of Bollywood' : Award-winning journalist Mohar Basu**
- जीवनी 'सलमान खान: बॉलीवुड के सुल्तान': पुरस्कार विजेता पत्रकार मोहर बसु
- **'Chunotiya Mujhe Pasand Hai', based on the life of Uttar Pradesh Governor Smt. Anandiben Patel : Pankaj Jani, Ashok Desai and Vinay Joshi**
- 'चुनोतिया मुझे पसंद है', उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती के जीवन पर आधारित है। आनंदीबेन पटेल: पंकज जानी, अशोक देसाई और विनय जोशी





**Ques: What is the Aadhaar-like unique identification proposed by the Transport Ministry for Electric Vehicle (EV) batteries?**

परिवहन मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरियों के लिए प्रस्तावित आधार-जैसी यूनिक पहचान क्या है?

- A) EVIN / ईवीआईएन
- B) Battery UID / बैटरी यूआईडी
- C) BPAN / बीपीएएन
- D) Green Battery ID / ग्रीन बैटरी आईडी
- E) e-Battery Aadhaar / ई- बैटरी आधार

**Answer:** Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- The Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) has proposed assigning an Aadhaar-like unique identification number to EV batteries.
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने EV बैटरियों के लिए आधार-जैसी यूनिक पहचान संख्या देने का प्रस्ताव रखा है।
- As per draft guidelines, battery manufacturers or importers will assign a 21-character Battery Pack Aadhaar Number (BPAN) to each EV battery.
- ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, बैटरी निर्माता या आयातक प्रत्येक EV बैटरी को 21-अक्षरों वाला बैटरी पैक आधार नंबर (BPAN) देंगे।
- The objective is to ensure end-to-end traceability of EV batteries across their entire lifecycle—from manufacturing or import to end-of-life recycling.
- इसका उद्देश्य बैटरियों की निर्माण/आयात से लेकर जीवन के अंत में रीसाइक्लिंग तक पूरी ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना है।
- The framework will promote efficient recycling and environmentally sound disposal of used batteries.
- यह ढांचा प्रयुक्त बैटरियों के कुशल रीसाइक्लिंग और सुरक्षित निपटान को बढ़ावा देगा।
- The move aligns with India's goals of clean mobility and development of a circular economy.
- यह पहल स्वच्छ गतिशीलता और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।

